भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2329

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में दूध उत्पादन

2329. श्री अमर शरदराव कालेः

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री संजय दीना पाटिलः

श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल दूध उत्पादन और कुल दूध प्रसंस्करण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में ग्रामीण किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध व्यवसाय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में जिले-वार कितने किसानों को प्रोत्साहन दिया गया है;

(घ) इस समय महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत डेयरी सहकारी समितियों की संख्या कितनी है और महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादित दूध का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पशुधन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश विशेष रूप से महाराष्ट्र में नए डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित करने/खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लाभ के लिए दूध और दूध उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस 2024) के अनुसार देश में वर्ष 2023-24 के दौरान कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारत में सहकारी डेयरियों की कुल प्रसंस्करण क्षमता 1033.64 लाख लीटर प्रतिदिन (मार्च 2023 तक) है।

(ख) और (ग) दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार महाराष्ट्र सहित पूरे देश में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

(ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)

(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

(iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर रही हैं। ये पहलें हस्तक्षेप दूध उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करती हैं तथा डेयरी पालन से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं। हालांकि, किसानों को सीधे तौर पर कोई आर्थिक सहायता प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय के अनुसार आज की तिथि तक महाराष्ट्र में पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियों की कुल संख्या 13984 है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र का जिलावार दूध उत्पादन अनुबंध में है।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) योजना के तहत निम्नलिखित प्रजनन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

1. राज्य के सोलापुर और सांगली जिलों में भैंसों की पंढरपुरी नस्ल के सुधार के लिए नस्ल चयन परियोजना। इस परियोजना में वीर्य उत्पादन के लिए पंढरपुरी नस्ल के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड बछड़ों के उत्पादन और वीर्य स्टेशनों को वितरण के माध्यम से भैंसों की भावी पीढ़ी की उत्पादकता में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

2. विदर्भ क्षेत्र के वर्धा, अमरावती और नागपुर जिलों में गोपशुओं की गाओलाओ नस्ल के सुधार के लिए नस्ल चयन परियोजना। इस परियोजना में वीर्य उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशनों को गाओलाओ नस्ल के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड बछड़ों के उत्पादन और वितरण के माध्यम से भावी पीढ़ी की उत्पादकता में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

3. विदर्भ-मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना: यह परियोजना भावी पीढ़ी के पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्य के साथ किसानों के पशुओं को गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने हेतु

500 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों का कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में किसानों को लगभग 2000 उच्च उत्पादन वाले दुधारू पशु निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

4. विदर्भ-मराठवाड़ा क्षेत्र में महिला किसानों द्वारा चलाई जा रही डेयरी में पशुओं के लिए सेक्स-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने हेतु कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क की स्थापना करना, ताकि उच्च आनुवंशिक गुणता वाली मादा बछड़ियों का अधिक संख्या (> 90%) में उत्पादन करके क्षेत्रों में दूध उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

5. राज्य के वाशिम-यवतमाल जिलों में महिला किसानों द्वारा चलाई जा रही डेयरी में पशुओं के लिए सेक्स-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने हेतु 100 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों का कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क स्थापित करना, ताकि उच्च आनुवंशिक गुणता वाली मादा बछड़ियों का अधिक संख्या (> 90%) में उत्पादन करके क्षेत्रों में दूध उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना में किसानों को लगभग 4000 उच्च उत्पादकता वाले दुधारू पशु निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

6. पशु समावेशन कार्यक्रम वाशिम यवतमाल परियोजना - चरण II: जिलों में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजना में दो जिलों में किसान लाभार्थियों को निःशुल्क 3000 उच्च उत्पादकता वाले दुधारू पशु शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

7. आईवीएफ भ्रूण (सेक्स सॉर्टेड वीर्य से उत्पादित) के माध्यम से गर्भाधान करवाने हेतु महाराष्ट्र राज्य में पुणे, कोल्हापुर और राजारामबापू दूध संघों के माध्यम से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (एबीआईपी-आईवीएफ-ईटी) का कार्यान्वयन। इस योजना के तहत किसानों को प्रति गर्भधान 5000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। परियोजना में किसानों के बीच उच्च उत्पादकता वाले पशुओं के प्रसार के लिए आईवीएफ तकनीक को सस्ती और स्वीकार्य बनाने की परिकल्पना की गई है।

चारे की उपलब्धता में सुधार के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. **चारा प्लस किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ):** महाराष्ट्र में पशुधन दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय **चारा प्लस किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन** योजना कार्यान्वित कर रहा है । इस पहल का उद्देश्य वहनीय लागत पर गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता बढ़ाना है, जिससे दूध उत्पादन में सुधार हो। एफपीओ स्थानीय व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं और हरे चारे, सूखे चारे, सिलेज, घास आदि के लिए संगठित और सुनिश्चित आपूर्ति श्रृंखला बनाकर डेयरी किसानों की मदद करते हैं।

   महाराष्ट्र राज्य में कुल 8 एजेंसियों (दूध संघ/अन्य एजेंसी) को 9 चारा प्लस एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) के रूप में नामोदिष्ट किया गया है। सभी एफपीओ पंजीकृत हैं और इनमें से 8 एफपीओ ने हरे चारे का उत्पादन और बिक्री, साइलेज की

बिक्री, सूखा चारा इकट्ठा करना और बेचना, तने की कटिंग की बिक्री आदि जैसे व्यावसायिक कार्यकलाप शुरू किए हैं।

सूक्ष्म (माइक्रो) प्रशिक्षण केन्द्रों (एमटीसी) की स्थापना: डेयरी किसानों को चारा उत्पादन, संरक्षण और डेयरी फार्म प्रबंधन के अन्य पहलुओं पर शिक्षित करने के लिए नागपुर, वर्धा और अमरावती जिलों में तीन एमटीसी स्थापित किए गए हैं। अब तक, 84 बैचों में लगभग 2023 डेयरी किसानों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

(च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) ने सूचित किया है कि वर्तमान में देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में नए डेयरी विज्ञान/डेयरी तकनीकी महाविद्यालय स्थापित करने/खोलने की कोई योजना नहीं है।

(छ) पशुपालन और डेयरी विभाग केंद्रीय क्षेत्र की योजना पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। एलएचडीसीपी का उद्देश्य पशु रोगों के लिए प्रोफाईलेक्टिक टीकाकरण, पशुचिकित्सा सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशुचिकित्सा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण से पशु स्वास्थ्य जोखिम को कम करना है। पशु स्वास्थ्य संबंधी पहलू से संबंधित ये उपाय दूध और दूध उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) नामक एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समिति की स्थापना की है। देश भर की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। एनसीईएल को गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ), भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति, भारतीय विपणन परिसंघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा प्रवर्तित किया गया है। सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं की वस्तुओं और सेवाओं का सीधा निर्यात करने और अन्य संवर्धन कार्यकलापों को करने के लिए एनसीईएल की स्थापना की गई है। एनसीईएल सहकारी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा। एनसीईएल के माध्यम से अधिक निर्यात से विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार संपर्कता बढ़ेगी, जिससे सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होगा और किसान सदस्यों को बेहतर लाभ मिलेगा।

*****

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिलावार दूध उत्पादन निम्नानुसार है:

महाराष्ट्र में जिलावार दूध उत्पादन (000 टन)			
जिले का नाम	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**
अहमदनगर	2077.82	2183.65	2194.40
अकोला	93.28	94.15	83.20
अमरावती	193.04	197.00	194.89
औरंगाबाद	331.82	345.25	323.80
बीड	345.96	378.24	420.20
भंडारा	130.31	150.25	155.67
बुलढाना	176.29	182.74	161.24
चंद्रपुर	66.66	89.50	76.10
धुले	193.46	201.87	237.57
गडचिरोली	43.90	49.58	55.33
गोंदिया	93.18	101.46	86.54
हिंगोली	94.29	96.40	88.65
जलगांव	461.65	468.86	525.75
जलना	156.82	181.97	172.65
कोल्हापुर	1167.25	1207.92	1089.56
लातूर	295.17	299.49	311.54
मुंबई	20.83	20.83	55.41
नागपुर	173.54	180.11	222.12
नांदेड़	283.33	289.61	275.36
नंदुरबार	89.75	96.96	103.74
नासिक	839.54	875.24	1042.04
उस्मानाबाद	452.95	445.87	528.75
पालघर	121.90	126.26	93.22
परभणी	127.74	130.97	123.15
पुणे	1768.55	1835.63	2005.99
रायगढ़	94.89	97.76	98.40
रत्नागिरि	63.99	67.70	66.27
सांगली	1062.73	1109.04	1228.05
सतारा	822.92	863.44	948.12
सिंधुदुर्ग	41.71	47.56	37.67
सोलापुर	1418.17	1474.78	1626.56
थाणे	121.41	123.16	117.07
वर्धा	86.68	91.91	106.85
वाशिम	64.47	66.83	66.58
यवतमाल	127.32	132.50	119.44
कुल महाराष्ट्र	**13703.32**	**14304.51**	**15041.86**